

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 जुलाई 2017—आषाढ़ 28, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्र. 17255-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 19 जुलाई 2017 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१७

## मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार ( भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना )

## संशोधन विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार ( भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना ) अधिनियम, १९८० को और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१७.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ४ सन् १९८०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (घ) में, अंक तथा शब्द “३१ दिसम्बर, २०११” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “३१ दिसम्बर, २०१४” स्थापित किए जाएं.

धारा ३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, खण्ड (दो) तथा (तीन) में, अंक तथा शब्द “३१ दिसम्बर, २०११” के स्थान पर पर अंक तथा शब्द “३१ दिसम्बर, २०१४” स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द “३१ दिसम्बर, २०११” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “३१ दिसम्बर, २०१४” स्थापित किए जाएं.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ४ सन् १९८०) की धारा ४ में उपबंध है कि ३१ दिसम्बर, २०११ को किसी नगरेत्तर क्षेत्र में, किसी कृषि-भूमि या उसके अनुलग्न में किसी भूमिहीन व्यक्ति के दखल में का कोई वासस्थान उक्त तारीख को ऐसे व्यक्ति में भूमिस्वामी अधिकारों में निहित हो गया समझा जाएगा बशर्ते कि वह उस तारीख के पूर्व एक या एक से अधिक वर्षों तक उसके कब्जे में रहा हो.

२. राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि कई भूमिहीन व्यक्ति, जो ३१ दिसम्बर, २०११ के पश्चात् ऐसे वासस्थान का कब्जा रखे हुए हैं जो राज्य के नगरेत्तर क्षेत्रों में कृषि-भूमि पर स्थित हैं या उससे अनुलग्न हैं, भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त नहीं कर सके हैं. कृषि-भूमियों में वासस्थान रखने वाले भूमिहीन व्यक्तियों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से मूल अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित किए जाने का विनिश्चय किया गया है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ७ जुलाई, २०१७

उमाशंकर गुप्ता

भारसाधक सदस्य.